Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 16, 2019 (ASADHA 25, 1941 SAKA)

General Review

सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार विभाग वर्ष 2017–18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 2 जुलाई, 2019

No. Admn./431/2015/1SIT/9267.—

विभाग डिजिटल इंडिया और इसके स्तम्भों के दृष्टिकोण के अनुरूप आईटी पहलों को शुरू करने में बहुत प्रगति कर रहा है। वित्त वर्ष 2017–18 के स्वीकृत बजट रूपये 12704.60 लाख था, जिसमें से विभाग ने रूपये 12697.19 लाख खर्च कियें हैं। खर्च में कमी का कारण, भारत सरकार से फण्ड का न मिलना और विभाग में रिक्त पदों को न भरना है। विभाग की राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाता है कि विभाग में कोई राजस्व स्कीम नहीं है और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निगम के कार्यों से प्राप्त आरटीआई/आईटी एक्ट तथा लाभांश के तहत प्राप्त फीस के रूप में राजस्व प्राप्तियां हैं, जिनसे वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 6,55,790 रुपये आए हैं।

विभाग के महत्वपूर्ण डिविजन

- **आईटी सोसाइटी** – ई–शासन सूचना प्रौद्योगिकी प्रवर्तन कोष समिति कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के आयोजन के साथ आईसीटी अवसंरचना स्टाफ की आईसीटी ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर विकास गतिविधियों के आयोजन में सहायक है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान, सोसाइटी ने कुल रूपये 4.72 करोड़ की आय अर्जित की। यह आय मुख्यतः विभिन्न बैंकों में रखी एफडीआर के ब्याज और बचत बैंक खाते पर ब्याज से प्राप्त हुई है। सरकार ने प्रदेश मे आईटी सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आईटी सोसाइटी भी स्थापित की है।

- **हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.के.सी.एल.)**

  वर्ष 2013 में आईटी का लाभ उठाते हुए शिक्षा और विकास में नया उदाहरण स्थापित करने के लिए एचकेसीएल की स्थापना की गई। प्रदेशभर में एचकेसीएल के 250 से अधिक प्राधिकृत अध्ययन केन्द्र हैं। वर्ष 2017–18 के लिए कम्पनी का कारोबार रूपये 1758.26 लाख (ब्याज आय सहित) और वर्ष 2017–18 के दौरान, निगम का कुल लाभ (कर से पहले) रूपये 602.99 लाख रुपये रहा।

- **हारट्रोन :** हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम (हारट्रोन) प्रदेश में इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है। यह आईटी सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर की खरीद, आईटी रोडमैप के प्रदर्शन में विभाग को सहायता प्रदान करती है तथा यह स्टेट वाईड ऐरिया नैटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) और स्टेट डाटा सैंटर (एसडीसी) के साथ आईसीटी अवसंरचना की रीढ़ के रूप में भी कार्य करती है। वर्ष 2017–18 के दौरान, निगम का कारोबार रूपये 5809.89 लाख (अनुमानित) तथा वर्ष 2017–18 के लिए कुल लाभ रूपये 913.39 लाख (अनुमानित) रहा।

- **एनआईसी :** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार का एक अग्रणी आईटी संगठन है। एनआईसी के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है, राज्य सरकार की तरफ से आईसीटी एप्लिकेशनस पर रणनीतिक नियंत्रण प्रदान करना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द (एनआईसी) राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों, बोर्डों, निगमों के लिए ई–शासन एप्लिकेशन के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

वर्ष 2018–19 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख नीचे है :–

- **स्टेट डाटा सेंटर (एसडीसी) :–** इस वर्ष के दौरान स्टेट डाटा सेंटर पर विभिन्न विभागों, संगठनों और ई–जिला परियोजनाओं की 75 एप्लिकेशनज को होस्ट किया गया है।
- **नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)/भारत नेट** :– वर्ष के दौरान, 5,803 ग्राम पंचायतों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य पूरा किया गया और 5,637 ग्राम पचायतों में अद्योपांत परीक्षण पूरा किया गया और 3,400 ग्राम पंचायतों में एलआईटी सक्रीय है।
- **अटल सेवा केन्द्र (एएसकेस)** :– प्रदेश में कुल 11,986 एएसकेज (ग्रामीण क्षेत्रों में 8,204 और शहरी क्षेत्रों में 3,782) केन्द्र पंजीकृत किए गये हैं। वर्ष के दौरान, प्रदेश में कुल 6,623 अटल सेवा केन्द्र कार्य कर रहे थे।
- **आधार नामांकन** :– वर्ष 2015 की जनसंख्या के आधार पर, प्रदेश में आधार परिपूर्णता 103 प्रतिशत रही। देश में राज्य दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष के दौरान, पांच वर्ष की आयु के नीचे के बच्चों के आधार कवरेज में हरियाणा का पहला स्थान रहा।
- **ई–जिला परियोजनाएं** :– वर्ष के दौरान, प्रदेश भर में 6,623 से अधिक कार्यरत एएसकेज और 135 ई–दिशा केन्द्रों के माध्यम से 24 विभागों से सम्बन्धित कुल 170 सरकार से नागरिक (जी2सी) ई–सेवाएं प्रदान की गई।
- **स्टार्ट–अप वेयरहाउस** :– विभाग ने युवा व्यवसायिक उद्यमियों के लिए नैसकॉम (एनएएसएससीओएम) के सहयोग से गुड़गांव में एनोवेशन परिसर की स्थापना का कार्य शुरू किया ।
- **आईटी कॉडर** :– वर्ष के दौरान, प्रदेश में ई–शासन पहलों के सुचारू क्रियान्वयन और अनुपालन के लिए राज्य में आईटी कॉडर सृजित करने का कार्य शुरू किया गया ।
- **पोलिसी** :– राज्य सरकार ने हरियाणा को डिजिटल क्रांति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए पारिस्थितिकी सृजन के लिए चार सैक्टरों में विशेष नीतियों की शुरूआत की और अधिसूचित किया। इनमें आईटी और ईएसडीएम पोलिसी 2017, उद्यमीएवं स्टार्ट–अप पोलिसी 2017, संचार एवं संयोजकता अवसंरचना पोलिसी 2017 एवं साइबर सुरक्षा पोलिसी 2017 शामिल है।
- **यूएमएएनजी (उमंग)** :– राज्य ने वर्ष के दौरान उमंग एप्प पर 10 विभागों, बोर्डों और निगमों की 107 सेवाओं का शुभारम्भ किया।
- **ई–ऑफिस प्रोजैक्ट (हरियाणा में रोल आउट)** :– ई–ऑफिस प्रोजैक्ट को हारट्रोन और सूचना प्रौद्योगिकी सचिवालय में रोल आउट किया गया । प्रदेश के मुख्य सचिव और 38 अतिरिक्त, मुख्य सचिव के लिए पायलट आधार पर ई–लीव और ई–टूर का शुभारम्भ किया गया।
- **कॉल सेंटर :–** प्रदेश में विभिन्न ई–शासन सेवाओं के लिए 100 सीटों वाले कॉल सेंटर की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आईटी/आईटीईस सैक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बीपीओ/आईटीईस के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।
- **सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया** :– पंचकूला क्षेत्र में आईटी उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचकूला में एक नये सॉफटवेयर टैक्नोलॉजी पार्क आफ इंडिया (एसटीपीआई) सेंटर की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। वर्ष के दौरान, एमओयू हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू की गई और इसे अंतिम रूप दिए जाने का कार्य अग्रिम चरण पर रहा।
- **ई.शासन अनुप्रयोगों में पुरस्कार**:– राज्य ने वर्ष 2017–18 के दौरान, विभिन्न आईटी/ई–शासन पहलों के लिए 32 अवार्ड/विशेष सम्मान पुरस्कार/प्रशंसा/सेवा मान्यता पुरस्कार प्राप्त किए।
- **जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सम्मेलन** :– वर्ष 2017–18 के दौरान, हारट्रोन द्वारा विभिन्न कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, इनमें 25 दिसम्बर, 2017 को सुशासन दिवस, 15 सितम्बर, 2017 को गुरुग्राम में डिजिटल हरियाणा समीट, साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए,सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय (आईएसएमओ), द्वारा लगभग 22 परीक्षण सत्रों का आयोजन करना शामिल है।

विभागाध्यक्ष :–

रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान निम्न अधिकारियों ने प्रशासनिक सचिव और सचिव का कार्यभार सम्भाला :–

(a) प्रशासनिक सचिव

(i) श्री देवेन्द्र सिंह, आईएएस 1.4.2017 से 31.3.2018

(b) सचिव/विशेष सचिव

(i) श्री विजयेन्द्रा कुमार, आईएएस 1.4.2017 से 31.3.2018

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार विभाग।

INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT, REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT 2017-18

The 2nd July, 2019

No. Admn./431/2015/1SIT/9267.—

The Department is taking huge strides in rolling out IT initiatives in line with the vision of Digital India and its pillars. The approved budget for financial year 2017-18 was Rs. 12704.60 lakh, out of which, department has incurred an expenditure of Rs. 12697.19 lakh. The shortfall in expenditure is due to non-receipt of funds from Government of India and also due to non-filling up of few vacant posts in the Department. With regard to revenue receipts of the department, it is highlighted that there is no Revenue Scheme in the Department and the revenue receipts are in the form of fees received under RTI/IT Act and Dividend received from the Corporation (s) functioning under the administrative control of the Department, which comes to Rs. 6,55,790/- during financial year 2017-18.

The key division of the Department:

- **IT Society:** Society for IT Initiative Funds for e-Governance is an instrumental in organization of workshops and seminars, ICT Infrastructure, ICT training of staff and software development activities. During the financial year 2017-18, the Society earned total income of Rs. 4.72 crores. This income was mainly on account of interest from FDRs kept with various banks and from interest on saving bank account. The Government has also set up District IT Society at District Level under the Chairmanship/ Presidentship of Deputy Commissioner concerned to promote IT Sector in the State.
- **Haryana Knowledge Corporation Ltd. (HKCL):** HKCL has been set up in the year 2013 to create new paradigm in education and development by leveraging IT. HKCL has more than 250 Authorised Learning Centres across the State. The turnover of the Company for the year 2017-18 was Rs. 1758.26 lakh (including interest income) and the net profit for the year 2017-18 (before tax) was Rs.602.99 lakh.
- **HARTRON:** Haryana State Electronics Development Corporation (HARTRON) is the nodal agency for promoting Electronics and IT Industry in the State. It provides support to departments in showcasing IT Roadmap, procurement of IT software and hardware and also acts as a backbone of ICT infrastructure with SWAN and SDC. The turnover of the Corporation for the year 2017-18 was Rs. 5809.89 lakh (Tentative) and the net profit for the year 2017-18 was Rs. 913.39 lakh (Tentative).
- **NIC:** National Informatics Centre is a premier IT organization of Government of India. One of the major responsibilities of NIC is to provide strategic control on ICT applications on behalf of State Government. NIC has been playing a major role in development of e-Governance applications for all important Department/Boards/Corporations of the State Govt.

The notable achievements of the Department in 2017-18 are mentioned below:

- **State Data Centre (SDC):** 75 applications of various departments/organizations and e-District projects have been hosted on State Data Centre during the year.

- **National Optical Fiber Network (NOFN)/BharatNet:** During the year, Optical Fiber Cable (OFC) laying was completed in 5803 Gram Panchayats end to end testing has been completed in 5637 GPs and 3400 GPs are LIT active.
- **Atal Seva Kendras (ASKs):** A total number of 11,986 ASKs (8,204 in rural areas and 3,782 in urban areas) has been registered in the State. A total number of 6,623 Atal Seva Kendras were transacting in the State during the year.
- **Aadhaar Enrolment:**Aadhaar saturation in the State was 103% based on the population 2015. State was at 2nd rank in the country. Haryana was at number one rank in Aadhaar coverage of children below age of 5 year during the year.
- **E-District Projects:** During the year, a total number of 170 Government to Citizen (G2C) eServices pertaining to 24 departments have been provided through more than 6,623 transacting ASKs and 135 e-Disha Kendras across the State.
- **Start-up Warehouse:** The department has initiated the work for setting up of innovation campus at Gurgaon in collaboration with NASSCOM for Young enterprising entrepreneurs.
- **IT Cadre:** The work to create an IT Cadre in the State for smooth implementation and sustenance of e-Governance Initiatives in the State was initiated and an IT Cadre Policy was notified during the year.
- **Policy:** The State Govt. launched and notified 4 sector specific policies to create an ecosystem to put Haryana on the path of digital revolution, these includes IT & ESDM Policy 2017, Entrepreneur & Startup Policy 2017, Communication & Connectivity Infrastructure Policy 2017, Cyber Security Policy 2017.
- **UMANG:** State has launched 107 services of 10 Departments, Boards and Corporations on the UMANG App during the year.
- **e-office** project (Rollout in Haryana): E-office was rolled out in Hartron and Secretariat of Information Technology. e-Leave and e-Tour has been launched on pilot basis for Chief Secretary and 38 Additional Chief Secretary of the State.
- **Call Centre:** The work for setting up of 100 seater Call centre for various e-Governance services has been initiated in the State. The main objective of the scheme is to create employment opportunities for the youth, through the BPO/ITES operations and to promote investment in IT/ITES sector
- **Software Technology Parks of India:** The work for setting up a new STPI Center at Panchkula for catering to the requirements of the IT industry in this area was initiated. The process of signing of MoU has been initiated during the year and is at the advanced stage of its finalization.
- **Award in e-Governance Applications**: The State has received 32 awards/Accolades/ Appreciations/ Recognition of Services during the year 2017-18 for various IT/e-Governance initiatives
- **Awareness Programmes/Workshops/Conference:** During the year 2017-18, various Workshops/ Seminars/awareness session were conducted by HARTRON, these includes Good Governance Day on 25th December 2017, Digital Haryana Summit on 15th September 2017 at Gurugram, around 22 training sessions conducted by Information Security Management Officer (ISMO), Haryana for building cyber security awareness.

Head of Department.

During the year under report the following officers held the charge of the post of Administrative Secretary and Secretary:-

(a) Administrative Secretary

(i) Sh. Devender Singh, IAS **1.4.2017 to 31.03.2018**

(b) Secretary/Special Secretary

(i) Sh.Vijayendra Kumar, IAS **1.4.2017 to 31.03.2018**

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Information Technology, Electronics and Communication Department.

57161—C.S.—H.G.P., Chd.